

अनुच्छेद 142

प्रलिस के ललल:

अनुच्छेद 142, सर्वोच्च न्यायालय, उपभोक्ता संरक्षण नलल, 2020, 'शक्तलल के पृथक्करण' का सललललत ।

मेन्स के ललल:

अनुच्छेद 142 ।

चरचा में कूल?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [अनुच्छेद 142](#) के तहत फैसला सुनाया कल 10 वर्ष के अनुभव वाले वकील और पेशेवर राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जलला मंऑों के अधलक्ष तथा सदस्य के रूप में नलललत के पात्र होंगे ।

- सर्वोच्च न्यायालय ने [उपभोक्ता संरक्षण अधनलल, 2019](#) की धारा 101 के तहत [उपभोक्ता संरक्षण नलल, 2020](#) के प्रावधानों को रदद करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जसलमें राज्य उपभोक्ता आयोगों एवं जलला मंऑों के सदस्यों हेतु करमश: 20 वर्ष और 15 वर्ष का नलूनतम पेशेवर अनुभव नरलधारतल कलल गया है ।

न्यायालय का फैसला:

- केंद्र सरकार और संबंढतल राज्य सरकारों को उपभोक्ता संरक्षण (नलललत हेतु योग्यता, भरती की वधल, नलललत की प्रकरलल, पद की अवधल, राज्य आयोग और जलला आयोग के अधलक्ष एवं सदस्यों का इस्तीफा तथा हटाने) नलल, 2020 में संशोधन करना होगा ताकल राज्य आयोग और जलला मंऑों के अधलक्ष एवं सदस्य के रूप में नलललत के लललकरमश: 20 वर्ष और 15 वर्ष के बजाय 10 वर्ष के अनुभव का प्रावधान कलल जा सके ।
- उपर्युक्त संशोधन कलल जाने तक स्नातक की डगलरी वाले वकील और पेशेवर जनलके पास उपभोक्ता मामलों, कानून, सार्वजनलकल मामलों, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणजलल, उदयोग, वतलत, प्रबंधन, इंजीनलरलल, प्रौदयोगलकी, सार्वजनलकल स्वास्थ्य या चकलतलसा में 10 वर्षों का अनुभव है, राज्य उपभोक्ता आयोग और जलला मंऑों के अधलक्ष एवं सदस्य के रूप में नलललत के पात्र होंगे ।
- न्यायालय ने उम्मीदवारों की पात्रता की जाँच करने के ललल लखलत परीक्षा और मौखलक परीक्षा (Viva Voce) का सुझाव भी दलल ।

अनुच्छेद 142 कल है?

परचलल:

- अनुच्छेद 142 [सर्वोच्च न्यायालय](#) को ववलकाधीन शक्तल प्रदान करता है कूलकल इसमें कहा गया है कल सर्वोच्च न्यायालय अपने अधलकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डकलरी पारतल कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबतल कसल भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनशलचतल करने के ललल आवश्यक हो ।

रचनात्मक अनुप्रयोग:

- अनुच्छेद 142 के वकलस के शुरुआती वर्षों में आम जनता और वकीलों दोनों ने समाज के वभलनलन वंचतल वर्गों को पूर्ण न्याय दललाने या पर्यावरण की रक्षा करने के प्रयासों के ललल सर्वोच्च न्यायालय की सराहना की ।
- ताजमहल की सफाई और अनेक वचलराधीन कैदलियों को न्याय दललाने में इस अनुच्छेद का महत्त्वपूर्ण योगदान है ।

न्यायलकल अतरलक के मामले: Cases of Judicial Overreach:

- हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय के कई नरलण्य हुए हैं जनलमें यह उन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है जो लंबे समय से न्यायपालकल के ललल ['शक्तलल के पृथक्करण' के सललललत](#) के कारण वर्जतल थे, जो कल ['संवधलन का मूल संरचना'](#) का हसलसा है । ऐसा ही एक उदाहरण है:

- **राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे शराब बिक्री पर प्रतिबंध:** केंद्र सरकार की अधिसूचना में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे शराब की दुकान खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए इस प्रतिबंध को 500 मीटर की दूरी तक सीमित दिया है।
- इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी राज्य सरकार की इस तरह की अधिसूचना के अभाव में न्यायालय ने प्रतिबंध को राज्य राजमार्गों तक बढ़ा दिया।
- **अनुच्छेद 142** को लागू करने के इस तरह के फैसलों ने न्यायालयों में नहि विविकाधिकार की शक्ति को लेकर अनश्चितता पैदा कर दी है, जहाँ व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की अनदेखी की जा रही है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य वधियों में अंतरविष्ट प्रतिबंध अथवा नबिंधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिबंध अथवा नरिबंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। नमिनलखिति में से कौन-सा एक इसका अर्थ हो सकता है? (2019)

- (a) भारत के नरिवाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का नरिवहन करते समय लयि गए नरिण्यों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- (b) भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा नरिमति वधियों से बाध्य नहीं होता।
- (c) देश में गंभीर वत्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बनि वत्तीय आपात घोषति कर सकता है।
- (d) कुछ मामलों में राज्य वधिनमंडल, संघ वधिनमंडल की सहमति के बनि वधि नरिमति नहीं कर सकते।

उत्तर: (b)

स्रोत: बज़िनेस स्टैण्डर्ड

वन प्रमाणन

प्रलिमिस के लयि:

वन प्रमाणन, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, वन प्रबंधन परिषद।

मेन्स के लयि:

वन प्रमाणन और मानक।

चर्चा में क्यों?

हाल के वर्षों में **जलवायु परिवर्तन** के साथ **वनों की कटाई** विश्व स्तर पर एक गंभीर रूप से संवेदनशील मुद्दा बन गया है, जिससे वन-आधारित उत्पादों के प्रवेश और बिक्री को वनियमति करने हेतु **वन प्रमाणन** अनिवार्य हो गया है।

- **वर्ष 2021 में ग्लासगो जलवायु बैठक** में 100 से अधिक देशों ने वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को रोकने का संकल्प लिया।

वन प्रमाणन:

■ आवश्यकता:

- ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण हेतु वन बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषति करते हैं जो वभिनिन आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से उत्सर्जति होती है।
- विश्व के अनेक देश ऐसे किसी भी उत्पाद के उपभोग से बचना चाहते हैं जो वनों की कटाई या अवैध कटाई का परिणाम हो।
- नतीजतन, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने संबंधित बाज़ारों में वन-आधारित उत्पादों के प्रवेश और बिक्री को नियंत्रित करने वाले कानून पारति कयि हैं, जिसके लयि वन प्रमाणन की आवश्यकता है।

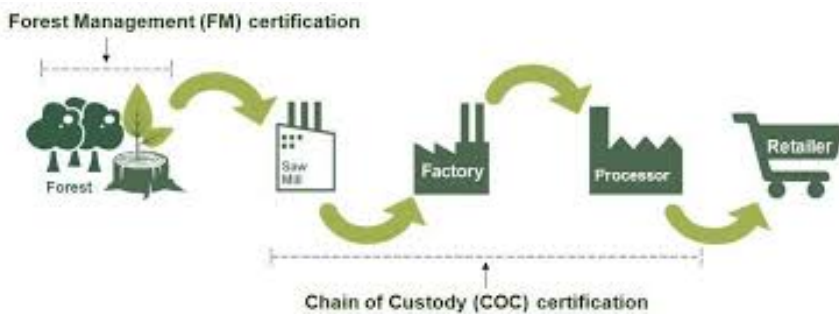
■ वन स्वीकृति:

- यह वन की नगिरानी, लकड़ी और लुगदी उत्पादों तथा गैर-इमारती वन उत्पादों को पहचानने एवं चहिनति करने का एक तंत्र है।

- यह वभिन्न प्रकार के उचित मानदंडों के वपिरीत सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पर्यावरण प्रबंधन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है।
- वनों और उन पर आधारित उत्पादों के **सतत प्रबंधन के लिये दो प्रमुख अंतराष्ट्रीय मानक हैं:**
 - फॉरेस्ट स्टीवरडशिप काउंसिल (FSC) द्वारा वकिसति
 - वन प्रमाणन समर्थन कार्यक्रम (PEFC) द्वारा वकिसति
- FSC प्रमाणीकरण **अधिक महंगा होने के साथ-साथ लोकप्रिय भी है।**

■ दो प्रकार के प्रमाणपत्र:

- वन प्रबंधन (Forest management-FM) एवं अभिरक्षा की शृंखला (Chain of Custody- CoC)
- CoC प्रमाणन का अभिप्राय प्रारंभिक दौर से लेकर बाजार आपूर्तिक संपूर्ण शृंखला में लकड़ी, जैसे- वन उत्पाद की ट्रेसबिलिटी की गारंटी देना है।



■ भारत में वन प्रमाणन:

- भारत में वन प्रमाणन उद्योग पछिले 15 वर्षों से कार्यरत है।
- वर्तमान में **केवल उत्तर प्रदेश में वन प्रमाणति है।**
 - उत्तर प्रदेश वन नगिम (UP Forest Corporation- UPFC) के 41 डिवीज़न वन प्रमाणन समर्थन कार्यक्रम (Programme for the Endorsement of Forest Certification-PEFC) द्वारा प्रमाणति हैं, जिसका अर्थ है कि PEFC द्वारा समर्थति मानकों के अनुसार उनका प्रबंधन किया जा रहा है।
 - कुछ अन्य राज्यों ने भी प्रमाणपत्र प्राप्त किये, लेकिन बाद में उन सभी ने सदस्यता वापस ले ली।
- भारत में वन प्रमाणन अभी भी प्रारंभिक चरण में है, इसलिये देश वन प्रमाणन के लाभों का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाया है।

भारत के वशिष्ट मानक क्या हैं?

- भारत **केवल प्रसंस्कृत लकड़ी के निर्यात की अनुमति देता है, प्रकाष्ठ (Timber) की नहीं।** वास्तव में भारतीय वनों से काटी गई लकड़ी आवास, फर्नीचर और अन्य उत्पादों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है।
- भारत के वन प्रत्येक वर्ष लगभग 50 लाख क्यूबिक मीटर लकड़ी का योगदान करते हैं। लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों **कलिंगभग 85% मांग वन क्षेत्र के बाहर के पेड़ों (Outside Forests- ToF) से पूरी होती है, जबकि लगभग 10% का आयात किया जाता है।**
- भारत की लकड़ी आयात लागत प्रतविर्ष **50,000-60,000 करोड़ रुपए है।**
- चूंकि ToF इतना महत्वपूर्ण है कि उनके स्थायी प्रबंधन हेतु नए प्रमाणन मानक वकिसति किये जा रहे हैं।
- PEFC के पास पहले से ही TOF प्रमाणन/सर्टिफिकेशन है और वर्ष 2022 में FSC ने भारत-वशिष्ट मानकों को जारी किया जिसमें ToF प्रमाणन शामिल था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन: ILO-UNICEF

प्रलिमिस के लिये:

मेन्स के लिये:

सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन: ILO-UNICEF ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन](#) (International Labour Organization- ILO) और [संयुक्त राष्ट्र बाल कोष](#) (United Nations Children's Fund- UNICEF) ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है- “More than a billion reasons: The urgent need to build universal social protection for children”, जिसके अनुसार, 4 में से सत्रह 1 बच्चा सामाजिक सुरक्षा द्वारा परिरक्षित है, जबकि शेष अन्य बच्चे गरीबी, बहिष्करण और बहुआयामी अभाव के शिकार हो जाते हैं ।

सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता:

- सामाजिक सुरक्षा एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है और गरीबी से मुक्त दुनिया हेतु एक पूर्व शर्त है ।
- यह दुनिया के सबसे कमजोर बच्चों को क्षमता प्राप्त करने में मदद देने का एक महत्वपूर्ण आधार भी है ।
- सामाजिक सुरक्षा भोजन, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बढ़ाने में मदद करती है ।
- यह [बाल श्रम](#) और [बाल विवाह](#) को रोकने में भी मदद कर सकती है एवं लैंगिक असमानता तथा बहिष्कार में अंतरनिहित कारणों को भी दूर कर सकती है ।
- यह घरेलू आजीविका का समर्थन करते हुए तनाव और यहाँ तक कि घरेलू हिंसा को भी कम कर सकती है ।
- यह आर्थिक गरीबी को खत्म कर उस कलंक और बहिष्करण को भी कम कर सकती है जिसका सामना कई गरीब बच्चे करते हैं साथ ही बचपन में महसूस की गई वंचना को "कम-से-कम" करने में मदद कर सकती है ।

रिपोर्ट के नबिर्कष:

■ समग्र परदृश्य:

- 0-18 वर्ष की आयु के 1.77 बिलियन बच्चों के लिये पारिवारिक नकद लाभ उपलब्ध नहीं है जो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक मौलिक स्तंभ है ।
- वयस्कों की तुलना में बच्चों के अत्यधिक गरीबी में रहने की संभावना दोगुनी होती है ।
 - लगभग 800 मिलियन बच्चे 3.20 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं और 1 बिलियन बच्चे बहु-आयामी गरीबी का सामना कर रहे हैं ।
 - 0-15 वर्ष की आयु के केवल 26.4% बच्चों को सामाजिक सुरक्षा द्वारा परिरक्षित किया जा सका है, शेष 73.6% बच्चे गरीबी, बहिष्करण (Exclusion) एवं बहुआयामी अभावों में जी रहे हैं ।
 - विश्व स्तर पर सभी 2.4 बिलियन बच्चों को स्वस्थ और खुश रहने के लिये सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है ।

■ सामाजिक सुरक्षा कवरेज:

- वर्ष 2016 से 2020 के मध्य विश्व के हर क्षेत्र में बाल और परिवार सामाजिक सुरक्षा कवरेज दर गिर गई या फरि स्थिर हो गई, जिससे कोई भी देश वर्ष 2030 तक पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज के तहत [सतत विकास लक्ष्यों \(SDG\)](#) को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता ।
 - लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों में कवरेज लगभग 51% से घट कर 42% हो गया है ।
 - कई अन्य क्षेत्रों में कवरेज या तो स्थिर है या इसमें कमी आई है ।

■ प्रभाव:

- अत्यधिक संकट के कारण बड़ी संख्या में बच्चों के गरीबी में होने की आशंका है, जिस वजह से सामाजिक सुरक्षा उपायों में तत्काल वृद्धि किये जाने की आवश्यकता होगी ।
- बच्चों के लिये सामाजिक सुरक्षा की कमी के तत्काल और दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं, इससे बाल श्रम एवं बाल विवाह जैसे अधिकारों के उल्लंघन की व्यापकता बढ़ जाती है, जिससे बच्चों की आकांक्षाओं तथा अवसरों में भी कमी आती है ।
- इसके अतिरिक्त इस अवास्तविक मानव क्षमता का सामान्य रूप से समुदाय, समाज और अर्थव्यवस्था पर अपरिहार्य प्रतिकूल तथा दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है ।

■ सामाजिक सुरक्षा का महत्व:

- [कोविड-19 महामारी](#) से पूर्व वयस्कों की तुलना में बच्चों के अत्यधिक गरीबी में रहने की संभावना दोगुनी से अधिक थी ।
- एक अरब बच्चे गरीबी के कई रूपों का अनुभव करते हैं जिनकी भोजन, पानी, स्वच्छता, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, स्कूली शिक्षा और

अन्य आवश्यकताओं तक पहुँच की कमी है।

- कोविड-19 महामारी ने संकट के समय में सामाजिक सुरक्षा के महत्त्व को प्रदर्शित किया।
- वशिव की लगभग प्रत्येक सरकार ने बच्चों और परिवारों की मदद करने के लिए या तो मौजूदा कार्यक्रमों का तेज़ी से अनुकूलन किया या नई सामाजिक सुरक्षा पहल की शुरुआत की।

- अनार्यों तथा बच्चों की बाल सहायता अनुदान (सीएसजी) राशि बढ़ाने के लिये दक्षिण अफ्रीका ने वर्ष 2022 में एक कल्याणकारी योजना बाल सहायता अनुदान (सीएसजी) टॉप-अप कार्यक्रम की शुरुआत की।
- राष्ट्रीय "पीएम केयरस फॉर चिल्ड्रन" योजना 10,793 पूर्ण अनार्यों और 151,322 अर्द्ध-अनार्यों के लिये उपायों का पैकेज है, जसि 31 भारतीय राज्यों में अधिनियमित किया गया था। अब तक 4,302 बच्चे इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं।

सुझाव:

- सभी बच्चों के लिये सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दशा में कार्रवाई करना नीतिनिर्माताओं हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिये, जनिहें उन कार्यक्रमों में भी शामिल किया जाना चाहिये जो बाल गरीबी की समस्या के समाधान की गारंटी प्रदान करते हैं।
- अधिकारियों को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के माध्यम से बाल लाभ प्रदान करने की भी सलाह दी जाती है जो परिवारों को महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं से जोड़ती हैं, जैसे गुणवत्ता वाली मुफ्त या सस्ती बाल-देखभाल।
- घरेलू संसाधनों को जुटाकर बच्चों के लिये बजट आवंटन बढ़ाकर, माता-पिता एवं अभिभावकों हेतु सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करके और अच्छे काम एवं पर्याप्त कर्मचारी लाभ की गारंटी देकर योजनाओं के लिये स्थायी वित्तपोषण हासिल करने की आवश्यकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न.अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मलेन 138 और 182 (2018) से संबंधित हैं:

- बाल श्रम
- वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिये कृषिप्रथाओं की अनुकूलता
- खाद्य कीमतों और खाद्य सुरक्षा का वनियमन
- कार्यस्थल पर लगी समानता

उत्तर: (a)

स्रोत : डाउन टू अर्थ